बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 36 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 14 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हाई कोर्ट याचिका पर विधानसभा का विरोध

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में बने कथित फांसीघर के नवीनीकरण पर खर्च को लेकर मचे विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने तलब किया है. इस समन के खिलाफ दोनों नेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसे विधानसभा सचिवालय ने भ्रमित करने वाली करार दिया है. फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट 24 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट में आप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शादन फरासत ने दलील दी कि फांसीघर का मामला विधानसभा के विधायी कामकाज से जुड़ा नहीं है इसलिए विशेषाधिकार समिति को इस पर कार्रवाई का अधिकार नहीं है.

दो नहीं तीन कार थी!...सुरक्षा एजेंसियों को तीसरी गाड़ी की तलाश; दिल्ली धमाके में एक और नया अपडेट

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में सोमवार शाम को हुए कार बम विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब तक दो संदिग्ध कारों की जानकारी सामने आने के बाद, गुरुवार को एक तीसरी कार के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसकी तलाश जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस तीसरी लापता कार को ढूंढने में जुटी है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल विस्फोटकों को ले जाने या संदिग्धों के भागने में किया गया होगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार शाम को लाल किला के पास एक सफेद हुंडई आई-20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की दुखद मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए थे। शुरुआती जांच में एक और संदिग्ध गाड़ी का पता चला था। जांच टीमों ने फरीदाबाद जिले में इस दूसरी गाड़ी, एक लाल फोर्ड इकोस्पोर्ट को बरामद करने में सफलता हासिल की थी। हालांकि, अब एक तीसरी कार, जिसके मारुति ब्रेजा होने की आशंका है, अभी भी लापता है। सूत्रों का कहना है कि लापता तीसरी कार का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा रेकी (टोही) करने या घटना के बाद भागने के लिए किया गया हो सकता है। इस आशंका के चलते, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मारुति ब्रेजा का पता लगाने के लिए दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। इस खुलासे के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है और हाई अलर्ट जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

विस्फोटकों के स्रोत, आरोपियों की पहचान और उनके मकसद का पता लगाने के लिए गहन पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। तीसरी कार के बरामद होने से जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है और यह उन संदिग्धों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फरीदाबाद के खंदावली गांव में जब खेतों में खड़ी एक लाल रंग की कार (ईकोस्पोर्ट) में विस्फोटक मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। यह वही लाल रंग की ईकोस्पोर्ट कार है जिसे दिल्ली धमाके में आतंकियों ने इस्तेमाल किया है। कार में विस्फोटक

मिलने की सूचना पर आनन-फानन एनएसजी, फॉरेंसिक टीम और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। कार के आसपास बने लगभग 10 घरों को खाली करा लिया और इलाके को सील कर दिया। मौके पर 400 से अधिक पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती की गई है, जो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद है। खंदावली गांव से लगभग 200 मीटर दूर खेतों में फहीम नाम के व्यक्ति के घर के पास एक लाल रंग की कार खड़ी थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि मंगलवार को सुबह कार को यहां खड़ा करने वालों में दो पुरुष और एक महिला शामिल थी, जिनमें फहीम का साला भी है।

फहीम का साला पेशे से कार मिस्त्री बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कार सर्विस कराने के दौरान फहीम के साले का संपर्क अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों और कुछ संदिग्ध आतंकियों से हुआ था। यह भी पता चला है कि फहीम की ससुराल धौज गांव में है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी भी स्थित है। इस खुलासे के बाद पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुट गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस घटना के मद्देनजर, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इलाके में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस विस्फोटक की प्रकृति और इसके पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और वे इस घटना को लेकर काफी चिंतित है। सुरक्षा एजेंसियां डॉ. उमर की गतिविधि और संचार का पता लगाने के लिए विस्फोट के दिन अपराह्न तीन बजे से शाम 6.30 बजे के बीच लाल किला क्षेत्र से मोबाइल डेटा का भी विश्लेषण कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि डॉ. मुजम्मिल ने अपने साथी डॉ. उमर नबी के साथ सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ की प्रकृति का पता लगाने के लिए कई बार लाल किले का दौरा किया था। टावर लोकेशन डेटा और आसपास के इलाकों से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी गतिविधियों की पुष्टि की गई है। ऐसा बताया गया है कि सोमवार को जिस कार में विस्फोट हुआ उसे डॉ. उमर नबी चला रहा था जो अल-फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर था।

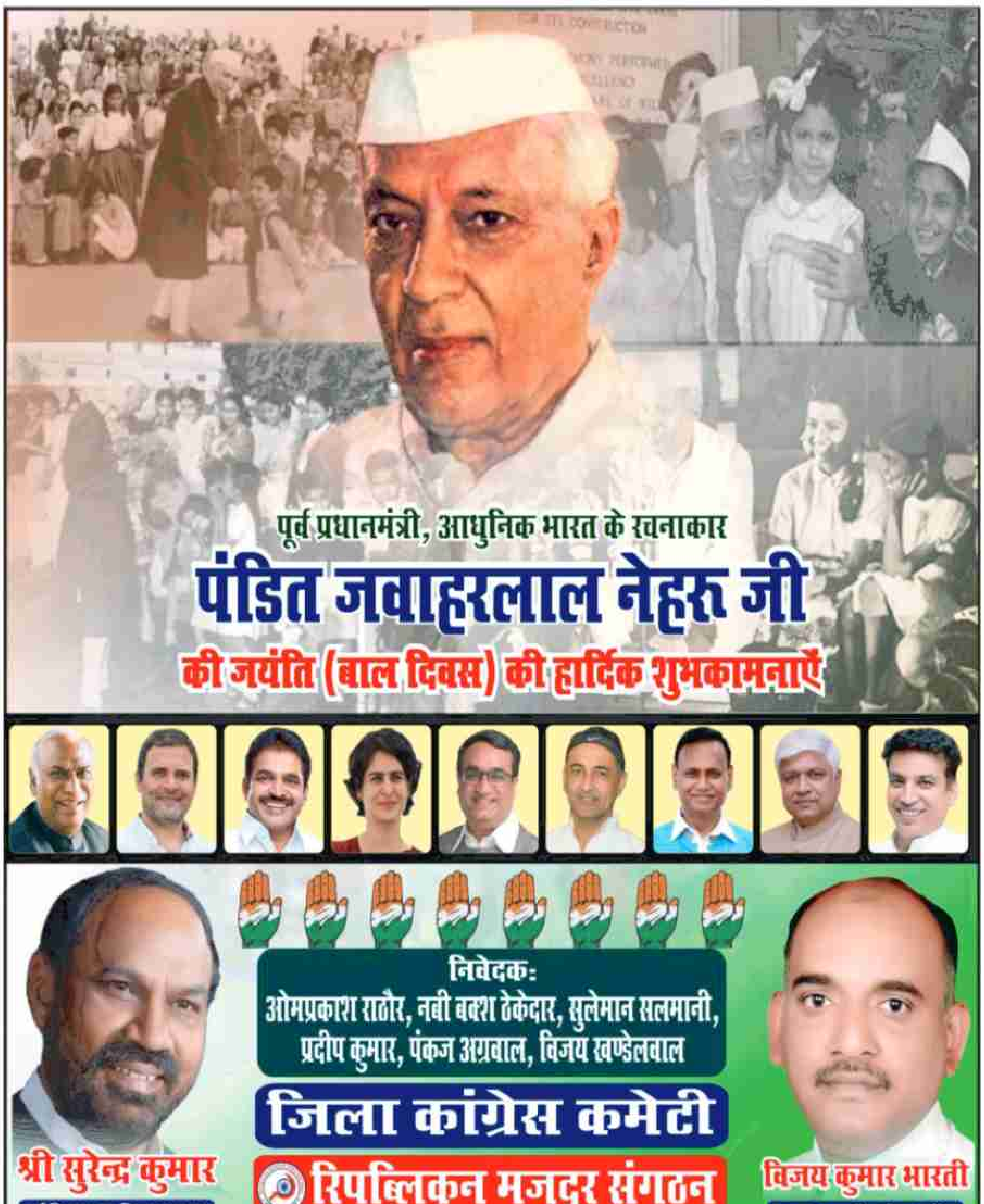

दिल्ली की जहरीली हवा में सुप्रीम कोर्ट का वकीलों को आदेश, वर्चुअल सुविधा है तो क्यों आ रहे सीधे, मास्क से क्या होगा!

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की और वरिष्ठ वकीलों से कहा कि वे सुनवाई में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हों क्योंकि सिर्फ मास्क पहनना ही पर्याप्त नहीं है। वायु प्रदूषण की स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए शीर्ष अदालत ने पूछा कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध थी, तो वरिष्ठ वकील प्रत्यक्ष रूप से क्यों पेश हुए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने वरिष्ठ वकीलों को तीखे लहजे में संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी यहाँ क्यों उपस्थित हो रहे हैं? हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है। कृपया इसका लाभ उठाएँ। प्रदूषण-इससे स्थायी नुकसान होगा।

दिल्ली में एक और विस्फोट की सूचना फर्जी, डीटीसी बस का टायर फटा; धमाके की आवाज सुन सहम गए थे लोग

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के महिपालपुर में गुरुवार सुबह एक डीटीसी बस का टायर फट गया, जिससे इलाके में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि, यह घटना ऐसे समय में हुई, जब दिल्ली के लोग लाल किला आतंकी विस्फोट को लेकर दहशत में हैं। वहीं, ऐसे में धमाके की आवाज सुनकर लोगों को लगा कि दिल्ली में एक और विस्फोट हो गया है। लेकिन हकीकत पता चलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। उधर, धमाके की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि डीटीसी की एक बस का टायर फटा है, जिस वजह से इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी। इसी धमाके की आवाज से कुछ लोग डर गए थे। पुलिस की ओर से कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कोई घटना होती है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। डीसीपी दक्षिण पश्चिम ने बताया कि महिपालपुर के रेडिसन होटल के पास विस्फोट की सूचना मिली और पुलिस बल को तुरंत मौके पर भेजा गया। कॉल करने वाले से संपर्क किया गया और बताया गया कि जब वह गुरुग्राम जा रहा था, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। स्थानीय पूछताछ में एक गार्ड ने बताया कि धौला कुआं जा रही एक डीटीसी बस का पिछला टायर फट गया था, इसलिए यह आवाज आई थी। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है।

स्कूल या फिर घर- अब दोनों जगह से होगी पढ़ाई! हाइब्रिड मोड में चलेंगी 5वीं तक क्लासेस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है और ग्रेप-3 की पाबंदियां पहले से ही लागू है। इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाना और उन्हें सुरक्षित शैक्षणिक विकल्प प्रदान करना है।अब 5वीं कक्षा तक के छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। यह पूरी तरह से अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या उन्हें घर से ऑनलाइन क्लासेस में शामिल कराना चाहते हैं। यह आदेश सीबीएसई सहित सभी अन्य बोर्डों के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों को हाइब्रिड मोड पर कक्षाओं की सुविधा देनी होगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि जो छात्र ऑनलाइन पढ़ना चाहें उन्हें स्कूल की ओर से जरूरी तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। यह फैसला बच्चों को स्वस्थ रखने और उन्हें सुरक्षित वातावरण में शिक्षा जारी रखने में मदद करेगा।

दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार, मंत्री आशीष सूद बोले- बॉर्डर पर उद्योग बढ़ना पॉल्यूशन की बड़ी वजह

बाहरी दिल्ली। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बृहस्पतिवार सुबह भलस्वा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया और उड़ान व निस्तारण को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। शहरी विकास मंत्री ने दिल्ली के साथ लगते राज्यों को राजधानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बॉर्डर पर उद्योग बढ़ने के कारण राजधानी में प्रदूषण बढ़ रहा है। नरेला और आसपास फैक्ट्री और चिमनियों की संख्या बढ़ी है। खरखौदा (हरियाणा) क्षेत्र में औद्योगिकीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगातार कूड़ा आ रहा है हाइड्रोलिक तरीके से वाहनों से कूड़ा खाली किया जा रहा है। यह धूल-धुएं का बड़ा स्रोत है। भलस्वा लैंडफिल साइट को हॉटस्पॉट घोषित किया जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार रही। सुबह साढ़े नौ बजे सीपीसीबी ने एक्यूआई 404 रिकॉर्ड किया, जो हवा की गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं, बिक्स एप आइक्यू एयर में 659 यानी और भी खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि हवा चलने की वजह से शाम तक इसके 400 से नीचे आ जाने की संभावना है। दूसरी तरफ मौसम में ठंडक भी जारी है। आज का न्यूनतम तापमान दर्ज 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रह सकता है।

मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया अव्यवहारिक, कहा- पशुओं के प्रति दया भावना जरूरी

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अदालत का आवारा पशुओं को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश 'अव्यवहारिक' है। गांधी ने कहा कि भारत को पशुओं के प्रति करुणा पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि नियंत्रण पर। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताई थी। अदालत ने ऐसे क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखने और राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे से मवेशियों को हटाने के निर्देश दिए थे। मेनका गांधी ने कहा कि अदालत के निर्देश करो लेकिन कोई कर नहीं सकता जैसे हैं। उन्होंने कहा कि कुत्ता हटाओ, बिल्ली हटाओ, बंदर हटाओ और शेल्टर में डालो यह संभव नहीं है। गांधी ने कहा कि देश में नगर निकायों के बीच तालमेल की कमी है और पशु संरक्षण में व्यावहारिक दृष्टिकोण जरूरी है। गांधी ने यह टिप्पणी नई दिल्ली में 'सिनेकिंड' नामक नई पहल के शुभारंभ के दौरान की। यह पहल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और उनकी संस्था 'पीपल फॉर एनिमल्स' द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य फिल्मों में करुणा और मानवीय संवेदनाओं को प्रोत्साहित करना है। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि फिल्मों की शक्ति समाज को प्रभावित करने में अपार है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले फिल्मों में जानवरों के साथ अत्याचार होता था, लेकिन अब आत्म-नियमन की जरूरत है। एफएफआई के अध्यक्ष फिरदौसुल हसन ने कहा कि 'सिनेकिंड' का उद्देश्य यह दिखाना है कि करुणा भी नायकत्व जितनी ही प्रभावशाली है।

लाल किला धमाका-जब आतंक ने बदल ली अपनी शक्ल-भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती नई चुनौती

वैश्विक स्तरपर दिल्ली, जो भारत की आत्मा का प्रतीक है,सत्ता, संस्कृति, और सुरक्षा का संगम। जब इसी दिल में लाल किला जैसे ऐतिहासिक, संरक्षित और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में विस्फोट होता है,तो यह केवल एक सुरक्षा चूकनहीं रह जाता, यह राष्ट्रीय चेतना को झकझोर देने वाला संदेश बन जाता है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ आतंकवाद केवल बंदूकों और बमों से नहीं,बल्कि ब्रेनवॉश, बौद्धिक आतंक और साइकोलॉजिकल रिक्रूटिंग के जरिए अपना विस्तार कर रहा है।यह धमाका उस नए युग की शुरुआत का संकेत है जिसमें आतंकी नेटवर्क ने पारंपरिक रणनीतियों को त्याग कर,सॉफ्ट टेररिज्म यानी मानसिक और वैचारिक आतंकवाद की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर वह डिजिटल और वैचारिक शक्ति का केंद्र बन रहा है, दूसरी ओर वही क्षेत्र आतंक के व्हाइट-कलर अवतार का मैदान भी बनता जा रहा है।लाल किला विस्फोट इस नई वास्तविकता की सबसे भयावह चेतावनी है, कि आतंक अब हमारी सीमाओं के बाहर नहीं,बल्कि हमारे विश्वविद्यालयों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दफ्तरों के भीतर प्रवेश कर चुका है।इसलिए भारत को अब पारंपरिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ एक नेशनल माइंड- सिक्योरिटी पॉलिसी भी तैयार करनी होगी,जो शिक्षा, सूचना, साइबर और वैचारिक सुरक्षा को एक समग्र रणनीति में जोड़े।साथियों, जब आतंकी हथियारों से नहीं, विचारों से हमला करते हैं,तो देश को भी केवल सुरक्षा बलों से नहीं, बल्कि सतर्क नागरिकों, जागरूक संस्थानों और सशक्त विचारधारा से जवाब देना होगा। यही उस अदृश्य युद्ध का सटीक प्रतिकार होगा जो आज भारत के मस्तिष्क पर लड़ी जा रही है। साथियों बात अगर हम लाल किला विस्फोट,एक प्रतीकात्मक हमला,एक गहरी साजिश को समझने की करें तो,लाल किला केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि भारतीय गणराज्य की गरिमा का प्रतीक है। जब इस धरोहर को निशाना बनाया गया, तो इसका उद्देश्य केवल भय फैलाना नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर प्रहार करना था।प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिले कि इस हमले की योजना अत्यधिक शिक्षित, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित और प्रोफेशनल लोगों ने तैयार की थी,यानी वह वर्ग, जिसे अब तक समाज सम्मानित नागरिक कहता आया है। यहीं से इस घटना की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है।यह केवल आतंकवाद नहीं, बल्कि व्हाइट कलर टेरर नेटवर्क का उदाहरण है,एक ऐसा नेटवर्क जो हथियार नहीं, बल्कि विचार, शिक्षा, तकनीक और मनोविज्ञान को हथियार बनाता है। इस नेटवर्क का खतरनाक पहलू यह है कि यह समाज की मुख्यधारा में रहकर, उसी के ताने-बाने को भीतर से नष्ट करता है। साथियों बात अगर हम व्हाइट कलर टेरर नेटवर्क, विश्वविद्यालय और पेशेवर संस्थान आतंकवाद की नई पोशाक को समझने की करें तो, पारंपरिक आतंकवाद में बंदूक, विस्फोटक और गुप्त ठिकाने शामिल होते थे, लेकिन अब यह युग समाप्त हो रहा है। नई पीढ़ी का आतंकवाद व्हाइट कॉलर हो गया है,यानी जो लोग जो शिक्षित हैं,डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, आईटी एक्सपर्ट हैं।ये लोग किसी सीमा पार के कैंप में नहीं,बल्किविश्वविद्यालयों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और थिंक टैंकों के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं। यह आतंकवाद अब रॉकेट लांचर से नहीं, बल्कि री- प्रोग्राम किए गए माइंड से काम लेता है।व्हाइट कलर टेरर नेटवर्क की यह अवधारणा आज के समय में वैश्विक स्तर पर सबसे खतरनाक मानी जा रही है। अमेरिका में लोन वुल्फ टेररिज्म, यूरोप में स्लीपर सेल प्रोफेशनल्स और दक्षिण एशिया में इंटेलेक्चुअल रेडिकलिज्म,यह सब एक ही श्रेणी में आते हैं।भारत में यह मॉडल धीरे-धीरे सक्रिय हुआ है,खासतौर पर सोशल मीडिया, डार्क वेब और विश्वविद्यालय परिसरों के जरिए। विश्वविद्यालय और पेशेवर संस्थान,वैचारिकरेडिकलाइजेशन के नए ठिकाने-लाल किला विस्फोट के संदिग्धों में कुछ विश्वविद्यालय- शिक्षित लोग शामिल होना कोई संयोग नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में विचारधारात्मक चरमपंथ ने धीरे- धीरे जड़ें जमाई हैं।कट्टरपंथी संगठन अब हथियारों की बजाय ब्रेनवॉशिंग पर अधिक निवेश कर रहे हैं। वे छात्रों को सिस्टम के खिलाफ, राज्य के विरोध में और सांस्कृतिक अस्मिता से दूर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।विश्वविद्यालयों का माहौल जहां स्वतंत्र चिंतन का केंद्र होना चाहिए, वहीं कुछ स्थानों पर यह सॉफ्ट रिक्रूटमेंट जोन में बदल गया है। ये युवा न तो सीधे आतंक मेंशामिल होते हैं, न ही हथियार उठाते हैं, बल्कि वे वैचारिक वाहक बन जाते हैं,जो आगे चलकर साइकोलॉजिकल टेरर के वाहक होते हैं। साथियों बात अगर हम सोशल मीडिया,आतंक का नया भर्ती तंत्र व बौद्धिक आतंकवाद को समझने की करें तो, 21वीं सदी का आतंकवाद अब जंगलों या पहाड़ों में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन और चैट रूमों में पलता है।लाल किला विस्फोट की जांच में सामने आया कि कुछ अभियुक्तों को ऑनलाइन इंडोक्ट्रीनेशन विदेशी प्रोफाइलों के माध्यम से की गई थी।यह नेटवर्कडिजिटल स्लीपर सेल्स की तरह काम करता है जहाँ व्यक्ति सामान्य नागरिक की तरह दिखता है,पर धीरे- धीरे उसे चरमपंथ की विचारधारा में खींच लिया जाता है।साइकोलॉजिकल टेररिज्म का यह डिजिटल चेहरा वैश्विक है। सीरिया, अफगानिस्तान, और अफ्रीका से लेकर यूरोप और अब भारत तक,यह नेटवर्क डिजिटल जिहाद, साइबर रिक्रूटमेंट और फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा के माध्यम से युवाओं को जोड़ रहा है।भारत में भी इस खतरे के संकेत स्पष्ट हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार केवल फिजिकल टेररिज्म पर नहीं,बल्कि साइबर-सोशल रेडिकलाइजेशन पर भी कठोर निगरानी रखे।बौद्धिक आतंकवाद,जब शब्द बनते है हथियार- आधुनिक आतंकवाद का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह अब केवल गोली से नहीं, बल्कि विचार से भी हत्या करता है।यह वही स्थिति है जब शिक्षित, सभ्य और प्रतिष्ठित लोग, अपने विचारों के माध्यम से युवाओं के मन में नफरत, विभाजन और हिंसा का बीज बो देते हैं।इसे ही सुरक्षा विशेषज्ञ बौद्धिक आतंकवाद या इंटेलेक्चुअल रेडिकलिज्म कहते हैं।लाल किला विस्फोट इसी प्रवृत्ति की परिणति है,जहां विचारधारा ने विस्फोटक का रूप ले लिया। आतंक अब उन विश्वविद्यालयों और प्रोफेशनल सर्किलों में पैठ बना रहा है जहां सोचने-समझने की शक्ति को हथियार बना दिया गया है।इस स्थिति से निपटने के लिए केवल सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर्याप्त नहीं, समाज, शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी जागरूक होना होगा। साथियों बात अगर हम वैश्विक संदर्भ, सुरक्षा तंत्र की चुनौती, दुनियाँ में बढ़ता व्हाइट कलर टेररिज्म को समझने की करें तो,लाल किला विस्फोट कोई अलग घटना नहीं है; यह उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में देखी जा रही है।अमेरिका में 9/11 के बाद यह महसूस किया गया कि कुछ उच्च शिक्षित इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने इस हमले की योजना बनाई थी।इसी तरह ब्रिटेन में 2005 का लंदन ब्लास्ट और फ्रांस में 2015 का पेरिस अटैक,दोनों में ऐसे लोग शामिल थे जो उच्च शिक्षित और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित थे।यह प्रवृत्ति बताती है कि आतंकवाद अब गरीबी,अशिक्षा या बेरोजगारी से नहीं, बल्कि विचारधारात्मक हाइजैकिंग से पैदा हो रहा है।भारत के लिए यह एक गंभीर चेतावनी है कि यदि समय रहते इस दिशा में वैचारिक और डिजिटल सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, तो आने वाले वर्षों में इंटेलेक्चुअल टेररिज्म सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।सुरक्षा तंत्र की चुनौती,जब दुश्मन हमारे भीतर हो-भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह नई परिस्थिति सबसे कठिन है।पहले आतंकवादी सीमाओं के पार से आते थे,पर अब वह हमारे बीच रहकर हमारे जैसा जीवन जीते हुए, हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं।ऐसे में पारंपरिक खुफिया प्रणाली पर्याप्त नहीं रह जाती। सुरक्षा तंत्र को अब साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, इंटेलेक्चुअल सर्विलांस और डिजिटल पैटर्न एनालिसिस जैसे आधुनिक तरीकों का उपयोग करना होगा।इसके साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉरपोरेट संस्थानों को भी सुरक्षा साझेदार बनाना होगा।नेशनल सिक्योरिटी अब केवल पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसी का विषय नहीं रहा;यह अब वैचारिक, तकनीकी और सामाजिक सुरक्षा का संयुक्त फ्रेमवर्क है।सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन, सबसे छिपा, सबसे खतरनाक रूप-सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को धीरे-धीरे, बिना किसी हिंसक प्रशिक्षण के, वैचारिक रूप से चरमपंथी बना दिया जाता है,यह प्रक्रिया महीनों नहीं, बल्कि वर्षों में होती है।

और व्यक्ति को अहसास तक नहीं होता कि वह एकविचारधारात्मक सैनिक बन चुका है।लाल किला धमाका इसी सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन की परिणति है।यह हमें बताता है कि आतंकी अब गोलियों की नहीं, बल्कि क्लिक की दुनिया में रहते है।

सम्पादकीय...

ममदानी की जीत

न्यूयार्क एक अद्भुत शहर है। दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए यह सपनों का शहर है, जहां सपने पूरे भी होते हैं। जनसंख्या 90 लाख के करीब है। प्रति परिवार वार्षिक आमदनी 75000डॉलर है। केवल आठ देश, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत, फ्रांस, यूके और इटली है जिनकी जीडीपी न्यूयार्क की 2.37 डॉलर की जीडीपी से अधिक है। न्यूयार्क का बजट 116 बिलियन डॉलर है। इसके मुकाबले हमारे सबसे बड़े शहर मुम्बई का बजट 8.9 बिलियन डॉलर (74.427 करोड़ रुपए) है। यहां 350000 करोड़पति हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध (या अप्रसिद्ध) डोनाल्ड ट्रम्प हैं ! न्यूयार्क में 32 लाख लोग ऐसे रहते हैं जिनका जन्म अमेरिका से बाहर हुआ है। शहर की आबादी का केवल 31% व्हाइट है। बाकी अश्वेत, अफ्रीकी, एशियन या दक्षिण अमेरिका के हिस्पैनिक लोग हैं। यही कारण है कि यह शहर पूंजीवाद की राजधानी होने के बावजूद अधिकतर उदारवादी और प्रगतिशील रहा है। न्यूयार्क के बाहर बंदरगाह में एक छोटे टापू में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (आज़ादी की प्रतिमा) है। उसके आधार पर एक पट्टिका है जिस पर कवि एम्मा लाजरस की कविता की यह पंक्तियां लिखी हुई हैं, मुझे अपनी थकी हुई, अपनी गरीब, अपने झुंड में जमा भीड़ दे दो जो आज़ादी से सांस लेने के लिए तरस रही है। सदियों से न्यूयार्क इन पंक्तियों को सार्थक करता आ रहा है। इस शहर को अप्रवासियों ने बनाया है। डोनाल्ड ट्रम्प खुद अप्रवासी परिवार से हैं लेकिन अब अमेरिका में सब कुछ बदल रहा है। अप्रवासियों को बताया जा रहा है कि आप का अमेरिका में स्वागत नहीं है। न्यूयार्क में गैर कानूनी ढंग से रह रहे लोगों की भरमार है। इनके बिना तो शहर चल ही नहीं सकता। न्यूयार्क के लोग ट्रम्प की नीतियों को पसंद नहीं करते। उन्होंने ट्रम्प का जवाब अनोखे पर लोकतांत्रिक तरीके से दिया है। उन्होंने भारी बहुमत से अपना मेयर एक 34 वर्षीय भारतीय मूल के मुसलमान जिनकी मां पंजाबी हिन्दू, प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता मीरा नायर हैं, को चुन लिया है। ट्रम्प आदत के मुताबिक़ चीखते-चिल्लाते रहे। धमकी दी कि अगर इसे चुन लिया तो न्यूयार्क की फ़ंडिंग बंद कर दूंगा, पर न्यूयार्क ने ज़ोहरान ममदानी को अपना मेयर चुन ट्रम्प को सीधा जवाब दे दिया। कुछ वर्ष पहले तक ज़ोहरान ममदानी एक रैपर थे। उन्होंने कभी भी अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की। न ही यह छिपाने की कोशिश की कि वह भारतीय है। जब वहां रह रहे बहुत से भारतवंशी खुद को अमेरिकियों से भी अधिक अमरीकी साबित करने के कोशिश में रहते है, ममदानी यह छिपाने की कोशिश नहीं करते कि अंदर से वह देसी है। दिवाली पार्टी में कुर्ता पहन,या नमस्ते कर,वह बता रहे है कि वह अपनी जड़ों को नकारने के लिए तैयार नहीं। अपने अभियान में उन्होंने बार-बार गांधी को उद्धृत करने से लेकर बालीवुड का सहारा लिया। जीतने पर अपने भाषण में उन्होंने जवाहर लाल नेहरू के देश की आज़ादी के समय दिए भाषण, इतिहास में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जहां हम पुराने से नए युग में कदम रखते है को भी याद किया। जब भाषण समाप्त हुआ तो कोई अंग्रेज़ी गाने की धुन नहीं, बालीवुड की धूम मचा ले धूम बज रही थी। ममदानी नहीं समझते कि अपनी पृष्ठ भूमि के बारे उन्हें किसी प्रकार से शर्मिंदा होने की जरूरत है। उनका कहना था कि न्यूयार्क अप्रवासियों का शहर रहेगा। मैं नौजवान हूं और मैं मुस्लिम हूं। मैं मुस्लिम होने के लिए माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हूं। अमेरिका जैसे देश में जहां आजकल 'दूसरों' के प्रति नफ़रत की लहर चल रही है, ममदानी का यह स्पष्ट कहना अर्थपूर्ण है। ट्रम्प के आने के बाद वहां भारतीयों के प्रति रवैया बदला है। जहां पहले हमें वहां की 'सक्सैस स्टोरी' माना जाता था, अब हमारे लोगों की सफलता ही बोझ बन गई है। वहां रह रहे भारतीयों के प्रति विद्वेष बढ़ रहा है। हेट-क्राइम बढ़ रहा है। इस माहौल में ज़ोहरान ममदानी की जीत का महत्व है, क्योंकि न्यूयार्क, आख़िर न्यूयार्क है। ममदानी क्यों जीते? असली कारण है कि उन्होंने आम अमरीकी की आर्थिक चिन्ताओं को राजनीतिक एजेंडे के ऊपर पहुंचा दिया। लोग परिवर्तन चाहते है। ट्रम्प भी परिवर्तन का वादा कर सत्तारूढ़ हुए थे, पर अपनी सनक और ईगो के कारण भटक गए। वह टैरिफ़ वॉर में फंस गए जिससे अमेरिका का कोई भला नहीं हुआ। चीजें महंगी हो रही है और आम आदमी परेशान है। दूसरी तरफ़ व्हाइट हाउस में गोल्ड प्लेटेड फ़िक्सचर लग रहे है। 20 करोड़ डालर, जो 17 अरब रुपए बनता है, का बॉलरूम बनवा रहे हैं, चाहे इस पर सरकारी खर्च नहीं हो रहा। दूसरी तरफ़ न्यूयार्क इतना महंगा है कि एक कमरे का किराया 5000 डालर है। लोगों की तकलीफ़ों के प्रति बेरुख़ी ट्रम्प की वर्तमान समस्याओं का कारण है। ममदानी ने फ्री बस सफ़र, सरकारी किराना स्टोर शुरू करने, किराए बढ़ने पर रोक, फ्री चाईल्ड केयर सुविधा देने का वादा किया है। वह समझ गए कि आम आदमी के लिए न्यूयार्क में रहना जेब से बाहर होता जा रहा है, इसलिए रियायतों का वादा कर रहे हैं। सुपर रिच पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी आम लोगों को पसंद आया है, पर आगे बहुत बड़ी चुनौती है। इसका नाम डोनाल्ड ट्रम्प है। ट्रम्प उन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उन्हें खतरनाक कम्यूनिस्ट करार दिया था। ट्रम्प समर्थकों ने भी ममदानी के खिलाफ नफरत भरा अभियान चलाया था। उनके नाम, पहनावा, मज़हब सब पर अशिष्ट प्रहार किया गया। ट्रम्प की तो सारी राजनीति ही डर और धमकियों पर आधारित है। न ही वह निजी तिरस्कार को भूलते हैं, इसलिए पूरी सम्भावना है कि ट्रम्प और उनके समर्थक ममदानी को फेल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। वहां रह रहे अप्रवासियों पर असामान्य सख्ती हो सकती है। वैसे भी न्यूयार्क को सम्भालना बहुत मुश्किल है। ममदानी के विजन की तारीफ़ करते हुए न्यूयार्क से अफ्रीकी मूल के लेखक तिबिता कनीने लिखते हैं कि न्यूयार्क पर शासन करना बेहद कठिन है क्योंकि गहरे जमे हुए हित विवेकपूर्ण सुधार नहीं होने देते। आदर्शवादी हर बार सफल नहीं रहते पर इस समय तो न्यूयार्क ने दुनिया को ज़बरदस्त संदेश दिया है कि ट्रम्प ही अमेरिका नहीं है।

भागीदारी में आगे, हिस्सेदारी में पीछे महिलाएं

अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी महिला मतदाताओं को रिझाने में सत्ता के दावेदारों ने कसर नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने चुनाव की घोषणा से ऐन पहले महिला सशक्तिकरण के नाम पर सवा करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए तो महागठबंधन ने 'माई-बहिन योजना' के तहत हर महिला को अढ़ाई हजार रुपए महीना देने का वायदा किया।

महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों का वेतन बढ़ा कर 30 हजार रुपए करने का वायदा भी मतदान से पहले कर दिया। महिलाओं पर इस चुनावी मेहरबानी का कारण समझना मुश्किल नहीं। 2010 से ही हर चुनाव में महिलाएं मतदान में पुरुषों से बाजी मारती रही हैं। 2010 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत जहां 51.5 ही रहा, 54.5 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले। 2015 में हुए अगले विधानसभा चुनाव में मतदान का यह अंतर और बढ़ गया। पुरुष मतदान का प्रतिशत 53.3 तक ही सुधरा तो महिलाएं 60.5 प्रतिशत पर पहुंच गईं। बेशक 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत में कुछ कमी आई लेकिन 54.5 प्रतिशत पुरुष मतदान के मुकाबले 59.7 प्रतिशत के साथ आगे वे ही रहीं। इस चुनाव में भी मतदान में महिलाओं के आगे रहने के संकेत हैं। हार-जीत मतदान से ही तय होती है। मतदान में महिलाएं आगे हैं तो जाहिर है कि सरकार के चयन में भी उनकी पसंद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा निर्णायक भूमिका अदा करती है। इसलिए भी कोई खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने में पीछे नहीं रहना चाहता। चुनावी आंकड़े और विश्लेषण यह संकेत भी देता है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता महिलाओं में अन्य राजनेताओं के मुकाबले ज्यादा है। बेशक महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और मतदान में बढ़ती उनकी भागीदारी देश और समाज के लिए सुखद संकेत है। वांछित परिणामों पर बहस हो सकती है, पर बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। पंचायत चुनाव में 35 प्रतिशत आरक्षण है तो पुलिस भर्ती में 50 प्रतिशत लेकिन बात जब विधानसभा और लोकसभा की चुनावी राजनीति में प्रतिनिधित्व की आती है तो तस्वीर निराशाजनक उभरती है। मसलन, इस विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीटों पर 2357 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं लेकिन महिला उम्मीदवारों की संख्या मात्र 258 ही है। संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के लिए वर्ष 2023 में 106वां संविधान संशोधन पारित करते समय अपनी प्रतिबद्धता दोहराने वाले राजनीतिक दल महिलाओं को कम टिकट के लिए 'जीत की संभावना' की कसौटी की आड़ लेते हैं।

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 370 महिलाओं को टिकट दिए गए लेकिन सिर्फ 26 यानी 7 प्रतिशत ही जीत पाईं जबकि पुरुष उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत 10 रहा। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जिन राजनीतिक दलों की अपनी जीत की संभावना कम रहती है, वे महिलाओं को टिकट देने में उदारता दिखाते हैं। 2022 में प्रियंका गांधी ने 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का नारा देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 148 महिला कांग्रेस उम्मीदवार उतारीं, पर मात्र एक जीत पाईं।

जीत की बेहतर संभावना वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति ऐसी उदारता कभी नहीं दिखाई। इस बार बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा 26 टिकट मायावती की बसपा ने दिए हैं। 25 टिकटों के साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी दूसरे नंबर पर है। ये दोनों ही सत्ता की प्रमुख दावेदार नहीं लगतीं। सत्ता के प्रमुख दावेदारों में भाजपा और जद-यू ने 13-13 टिकट दिए हैं तो राजद ने 11, कांग्रेस के 61 उम्मीदवारों में 5 महिलाएं हैं। चिराग पासवान की लोजपा (आर) ने 29 में से 6 उम्मीदवार महिलाएं उतारीं लेकिन एक का नामांकन रद्द हो गया। एक और सच यह भी है कि जीत की संभावना वाली सीटों पर टिकट में अक्सर राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को ही मौका मिलता है। मसलन, जीतनराम मांझी ने अपने हिस्से आईं 6 सीटों में से 2 पर महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से एक उनकी समधन ज्योति देवी हैं तो दूसरी बहू दीपा। राजग में 6 सीटों वाली एक और पार्टी रालोमा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया है।

दरअसल यही महिला सशक्तिकरण की चिर-परिचित राजनीतिक शैली बन गई है। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद चुनावी राजनीति में उनकी घटती हिस्सेदारी हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर ही सवालिया निशान है। बिहार में 2010 में 34 महिलाएं जीत कर विधानसभा पहुंची थीं। 2015 में यह संख्या घट कर 28 रह गई तो 2020 में 26। वैसे चुनावी लोकतंत्र में आधी आबादी की बढ़ती भागीदारी और घटती हिस्सेदारी की यह विडंबना राष्ट्रव्यापी है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा था। कमोबेश यही कहानी 2019 के लोकसभा चुनाव की रही लेकिन आजादी के बाद से ही उनकी जीत का प्रतिशत घटता जा रहा है। 1957 में चुनाव लड़ने वाली 45 महिलाओं में से 22 जीत कर लोकसभा पहुंच गई थीं लेकिन 2024 में चुनाव लड़ने वाली 800 महिलाओं में से मात्र 74 ही जीत पाईं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आधी आबादी की यह तस्वीर देश के राजनीतिक नेतृत्व से ईमानदार आत्मविश्लेषण और प्रतिबद्धता की मांग करती है।

तिरछी नज़र : अगले जनम मुझे मुचुआ ही कीजो

छोटा पोता मेरे घर के क्लिनिक से मेरा स्टेथो उठा लाया और मेरे सीने पर लगा कर बोला, दादू, जरा जोर जोर से सांस लो। मैं उसे बहलाने के लिए जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर मेरी ओर देख कर बोला, दादू, डॉक्टर ऐसे ही करते हैं ना। मैं भी डॉक्टर बनूंगा। मैंने कहा, डॉक्टर मत बनना। निन्यानवे को ठीक करो और एक को न कर पाओ तो लोग तोड़फोड़ करने लगते हैं। अगले दिन वह लहरा लहरा कर दौड़ रहा था। मेरे पास आ कर बोला, दादू मैं तो पायलट बनूंगा। हवाई जहाज उड़ाऊंगा। आपको और दादी को मुफ्त में दुनिया की सैर करवाऊंगा। मैंने कहा, पायलट मत बनना। हवाई जहाज गिरने की स्थिति में लोग हवाई जहाज बनाने वाली कम्पनी को बचाने के चक्कर में पायलट को दोष देने लगते हैं। उससे अच्छा तो ऑस्ट्रोनोट बन जाना। उस पर कोई गुण दोष नहीं आता है। रॉकेट उड़ जाए तो सरकार जी की वाही वाही, नहीं उड़े तो वैज्ञानिकों का दोष। फिर एक दिन कहीं से एक सीटी ले आया। उसे बजा बजा कर बोलने लगा, जागते रहो, जागते रहो। बोला मैं वॉचमैन बनूंगा। सबकी चौकीदारी करूंगा। मैंने समझाया, बेटा चौकीदार मत बनना। आजकल चौकीदार बहुत बदनाम है। लोग कहते है कि 'चौकीदार ही चोर है'। वही तो खबर देता है, कहां चोरी करनी है और कैसे चोरी करनी है। उसकी मिलीभगत के बिना चोरी हो ही नहीं सकती है। दो तीन दिन बाद आ कर बोला, दादू, दादू, मैं तो वोट चोर बनूंगा। पिछली शाम को ही गली में वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली निकली थी। मैंने कहा, यह तो ठीक है बेटा। वोट चोर न जाने क्या से क्या बन गए हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री। यहां तक कि सरकार जी भी बन गए हैं। पर बेटे, इनसे ऊपर भी एक है। तुम वही बनना। वह है, मुचुआ मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त। विपक्ष कहता है कि वही वोट चोरी का सरगना है। उसकी सहमति के बिना वोटचोरी हो ही नहीं सकती है। वही एक पते पर दो सौ, चार सौ वोट बनवा सकता है। वही एक फोटो पर सौ सौ फर्जी वोट बना सकता है। उसी ने शून्य नंबर के मकान का आविष्कार किया है। यह उसी के अधिकार क्षेत्र में है कि वह लाखों लोगों के नाम काट दे और लाखों के नाम जोड़ दे। वही है जो यहीं के नागरिकों की नागरिकता नकार सकता है और विदेशी मॉडल को यहीं का वोटर कार्ड प्रदान कर सकता है। एक बात और बेटा। उसको तो कोई फंसा भी नहीं सकता है। जो कुछ वह करे, चाहे वोट जोड़े या वोट काटे, चाहे जितने मर्जी नकली वोट डलवा दे, चाहे वोटिंग खत्म होने के बाद भी वोट बढ़वाता रहे, चाहे जीते हुए को हारा और हारे हुए को जीता घोषित कर दे, ये उसकी मर्जी। इस चुनाव के महाभारत में वह जिसके साथ है, वही जीतता है। वह सर्वशक्तिमान है। उसके ऊपर तो उच्चतम न्यायालय भी नहीं है। बल्कि वह उच्चतम न्यायालय से ऊपर है। उसे किए की कोई सजा नहीं है। ऐसा हमेशा से नहीं था, ऐसा नियम सरकार जी ने हाल में ही बनाया है।

ऋण के जाल में फंसे देशों से भारत के राज्यों को मिलती है सीख

विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगाने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 330 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अविकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े है तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति, अधिक ब्याज दर, आय में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते है परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते है। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल है- जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)। ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था। भारत में भी कुछ राज्य फ्रीबी के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे है। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे है और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है। सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किस्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है।

किन परिस्थितियों में, कितने प्रकार की, कितनी और किस स्तर तक लोक लुभावन घोषणाएं की जानी चाहिए, इस सम्बंध में अब नियम बनाने का समय आ गया है। वैसे यदि ऋण को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो अधिक ऋण-सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बुराई नहीं है परंतु जब ऋण लेकर इसे अनुत्पादक कार्यों जैसे मुफ्त बिजली एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाता है तो इसका राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चुनावों के वादे पूरे करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण लिए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पंजाब की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। देश के कई राज्य आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए है कि इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद यदि समय पर नहीं पहुंचाई जाती तो इन राज्यों की स्थिति भी अर्जेंटीना, श्रीलंका अथवा ग्रीस जैसी बनती दिखाई देती। कुछ राज्यों की स्थिति तो यह है कि इनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उनकी कुल आय का 90 प्रतिशत भाग इन खर्चों पर उपयोग हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करने को कुछ बचता ही नहीं है। अब इन राज्यों की आय कैसे बढ़े? इन राज्यों द्वारा लगातार की जा रही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण इन राज्यों के खर्चे लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के खर्चों को करने के लिए नित नए ऋण लिए जा रहे है और इन ऋण राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाने के कारण ये राज्य अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर पा रहे है। इस प्रकार ये राज्य डेट ट्रैप की स्थिति में फंसते जा रहे हैं। आय का 25 से 30 प्रतिशत भाग ऋण का ब्याज भुगतान करने में ही खर्च हो रहा है। पंजाब तो अब आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। इसी तरह राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की स्थिति भी बिगड़ रही है। अगर राज्य पूंजीगत खर्च नहीं कर रहे है तो अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे है। इस प्रकार तो भविष्य में इन राज्यों की विकास दर भी रुक जाने वाली है। विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगाने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 330 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। [illegible]

दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च

शहीद स्थल पर पहुंच मृतकों को दी श्रद्धांजलि

फतेहपुर।

आज कांग्रेस कार्यालय ज्वालागंज में दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को लेकर कांग्रेसियों ने एक शोक सभा का आयोजन कर घटना में गगन दुःख व्यक्त किया एवं मृतकों की आत्म शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में दुख व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि अब भाजपा सरकार की विफलता सड़कों पर उतर आई है अब ऐसा प्रतीत होता की देश बिना किसी सरकार के चल रहा है उन्होंने आगे कहा कि नौ मई 2025को प्रधानमंत्री का व्यक्तव्य कि अब कोई भी आतंकवादी घटना युद्ध मानी जाएगी एक कोरा संदेश साबित हुआ है जो महज जनता को गुमराह करने वाला है। शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने कहा कि देश के ग्रह मंत्री चुनाव व सरकार बनाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है साथ ही रक्षा मंत्री तो शायद देश में कोई है ही नहीं सबकुछ भगवान भरोसे चल रहा है जो अत्यंत दुखद है। शोक सभा के उपरांत सभी कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर ठा. दरियाब सिंह की प्रतिमा तक मार्च कर वहां मौन रखा।

श्रद्धांजलि सभा में संतोष कुमारी शुक्ला, शेख एजाज अहमद,ई. देवी प्रकाश दुबे, राजीव लोचन निषाद, राम नरेश महराज, अनुराग नारायण मिश्र, सैयद सहाब अली, आदित्य श्रीवास्तव, चौधरी मोइन रइन ,अकरम काले, नौशाद अहमद, ओसाफ़ अहमद,डॉ हमीद अहमद, नसीम अंसारी, अमीर उज्जमा, रमजान अहमद, अजय बच्चा, कौशल कुमार शुक्ला, नज़मीकमर, हम्माद हुसैन, असलम, आदि लोग मौजूद रहे।

नन्हें मुन्नें बच्चों ने नृत्य ने मोहा मन

बिलारी।

एस.बी.एस. सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें नर्सरी से कक्षा 2 तक के लगभग 37 बच्चों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती डिंपल सक्सेना द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके किया गया साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत करने वाले बच्चे कृषवी ,अदिति ,अन्वी, आराध्या, घनिष्का, राधिका, का कुल, लवीना, अदिति, काश्वी, माहिरा , आयशा, नीति, मिस्टी, सृष्टि ,अरीशा, शानवी, आव्या, बतूल ,आयशा, अक्षरा, कृष, आयजा ,उजायफा, मोहम्मद, आरुषि, परिधि, अनुष्का, मिस्टी, गौरी और रीति आदि थी। ग्रुप ए में कक्षा एलकेजी और यूकेजी के बच्चों ने भाग लिया जिसमें यू.के.जी.की काकुल प्रथम

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती डिंपल सक्सेना द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके किया गया साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ भी किया गया।

एल.के.जी. की अन्वी द्वितीय और एल.के.जी. की ही कृस्वी तृतीय स्थान पर रही ,घनिष्का और काशवी को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रुप बी में कक्षा एक और दो के ब'चों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किये जिसमें अनुष्का कक्षा 2 की प्रथम अवसरा कक्षा 2 की द्वितीय और किसा कक्षा 2 की तृतीय स्थान पर रही हिती और नीति को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संयोग वशिष्ठ ने एवं प्रबंधक राजीव सहाय ने संयुक्त रूप से विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया एवं विजेता बच्चों को बधाई दी एवं अन्य सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कुल के साथ सम्पन्न हुआ अब्दुल्लाह शाह का उर्स

मुरादाबाद। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम हाथीपुर चित्तू में रविवार को हजरत अब्दुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का 89 वा दो रोजा उर्स का रविवार की शाम को कुल शरीफ के साथ समापन हो गया। जिसमें दूर दराज से आए अकीदतमंदों के साथ-साथ हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने की शिरकत, मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए मांगी गई दुआएं। गुरूवार को दरगाह शरीफ आने वाले जायरीनों के लिए लंगर का भी अहतमाम भी किया गया था। गौरतलब है कि हाथीपुर चित्तू स्थित हजरत अब्दुल्लाह शाह का 89 वा उर्स बुधवार से गुल व चादर पोशी कर मुल्क व कौम तरक्की की दुआ के साथ शुरू हुआ था।। हजरत अब्दुल्लाह शाह का यह 89 वा उर्स मनाया गया। हजरत अब्दुल्लाह के दरगाह पर दूर दराज से लोग आते हैं और चादर व गुल पोशी करते हैं लोगों अकीदा है की यहां पर जो भी जायज़ दुआएं मांगी जाती हैं वह पूरी होती हैं। जायरीन यहां पर नजरों नियाज भी करते हैं?। रविवार को × बजे कुल शरीफ का आयोजन किया गया कुल शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह शाह दरगाह के स'जादा नशीन हाजी नौशे मियाँ और इमाम हाफिज कमर आलम ने दुआ कराई। इस मौके पर मुख्य रूप से मुहम्मद जान तुर्की रियासत हुसैन फिरासत चौधरी हाजी बाबू , अरहान पाशा , गुड्डू पाशा, मजरुल , मासूम अली, बाबू, नाज़िर हुसैन, मुहम्मद इस्लाम, ,सहित आदि लोग मौजूद थे।

दिघिया निषाद बस्ती में सड़क न होने से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित, सांसद से लगाई गुहार

मांडा(प्रयागराज)।

प्रयागराज के मांडा विकासखंड में स्थित दिघिया निषाद बस्ती आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है।

बरसात के दिनों में यहाँ का मुख्य मार्ग कीचड़ और जलभराव से भरा रहता है, जिससे ग्रामीणों का स्कूल, अस्पताल और बाज़ार तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने वर्षों से इस समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर गुरुवार को लोकसभा सांसद उज्ज्वल रमन सिंह से मुलाकात की।

इस अवसर पर बस्ती निवासी विवेक कुमार ने बताया कि बरसात के समय आवागमन कठिन हो जाता है और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रभावित होती है। वहीं, विजय बहादुर ने कहा कि बृजलाल निषाद के घर से उनके घर तक सड़क का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मौजूदा रास्ता बरसात में चलना मुश्किल कर देता है। मुलाकात के दौरान ग्राम प्रधान मंगला प्रसाद पाल, जोखू निषाद, अजय कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने सांसद से निवेदन किया कि बस्ती के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने ग्रामीणों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग से संपर्क कर सड़क निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द शुरू कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि इस वर्षों पुरानी समस्या का समाधान शीघ्र हो और ग्रामीणों को राहत मिल सके। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सड़क निर्माण से न केवल उनकी यात्रा सुगम होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की ज़रूरतों तक पहुँच भी आसान हो जाएगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह कदम बस्ती के विकास और जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लापरवाह अफसरों से सीडीओ ने तलब किया स्पष्टीकरण

मुरादाबाद। ब्लॉक मिशन प्रबंधक ठाकुरद्वारा की विभागीय कार्यों में लापरवाही और अधिकारियों के निर्देशों के प्रति उदासीनता के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी ने स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। संतोष जनक जवाब न दिए जाने की दशा में इनके विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश रा'य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के 07 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद भी ब्लॉक मिशन प्रबंधक ठाकुरद्वारा श्री हरीश प्रताप सिंह की उदासीनता की वजह से विभागीय कार्य में प्रगति अत्यंत धीमी मिली। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक मिशन प्रबंधक ठाकुरद्वारा द्वारा उ'चाधिकारियों के समय समय पर जारी पत्रों का जवाब देने और अनुपालन करने में भी लापरवाही बरती जा रही है।

सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों का प्राथमिकता के साथ करें भुगतान: डॉ. रतन पाल सिंह

विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सभापति डॉ. रतन पाल सिंह ने समिति के सदस्य विजय बहादुर पाठक, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त और एमएलसी गोपाल अंजान की उपस्थिति में मुरादाबाद शहर स्थित सर्किट हाउस के सभागार में जिलाधिकारी अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल और मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी सहित जनपद के अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस विभाग, अग्निशमन, नगर निगम, खाद्य सुरक्षा, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग, जल निगम (नगरीय), लोक निर्माण विभाग आदि से संबंधित अधिकारियों से उनके कार्यालय से सेवानिवृत हो चुके कार्मिकों की पेंशन, ग्रेज्युटी सहित अन्य विभिन्न देयकों की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की।खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सभापति ने सहायक आयुक्त (खाद्य) से वर्ष 2017 से अब तक लिए गए नमूनों के सापेक्ष निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई कार्यवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की साथ ही दीपावली के दौरान खाद्य पदार्थों में हानिकारक मिलावट को रोकने के लिए विभाग स्तर से किए गए प्रयासों और कार्रवाई के बारे में भी समीक्षा की। सहायक आयुक्त (खाद्य) ने बताया कि 01 अप्रैल 2025 से अब तक 586 नमूने लिए गए हैं, सभापति ने जिलाधिकारी से कहा कि वे टीम बनाकर 2017 से अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में लिए गए नमूनों के आधार पर लंबित प्रकरणों का समाधान कराएं साथ ही कार्रवाई में विलंब होने के संबंध में अधिकारियों की भूमिका की भी कमेटी के माध्यम से जांच कराई जाए। विद्युत विभाग में लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान सभापति ने अधीक्षण अभियंता से बिजनेस प्लान 2025-26 के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि बिजनेस प्लान तैयार करने के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी अनिवार्य रूप से लिया जाए तभी आमजन की समस्याओं का समाधान और स्थानीय जरूर के अनुरूप बेहतर प्लान तैयार होगा। सभापति ने कहा कि कार्यालय स्तर पर सेवानिवृत कर्मचारियों के देयकों के भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए साथ ही मृतक आश्रित के प्रकरणों में भी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यथाशीघ्र समाधान होना चाहिए।

भारतीय मंदिर ऊर्जा, संतुलन और आत्मोन्नति के केंद्र

मुरादाबाद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रो. राजमल जैन बोले, भारतीय मंदिर केवल पूजा के स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा, संतुलन और आत्मोन्नति के केंद्र हैं। मंदिर समाज के नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। मंदिरों की पिरामिडीय संरचना और खगोलीय संरेखण को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हुए, उन्होंने आयोनिक और आइकोनिक प्रतिनिधित्व के जरिए मूर्त और अमूर्त स्तर पर आस्था और चेतना के गहरे संबंध की विस्तार से व्याख्या की। प्रो. जैन ने कहा, मंदिर भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला आत्मबोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं, जो शांति परंपरा की प्रतिमाएँ आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संबंध को दर्शाती हैं। प्रो. राजमल टीएमयू के इंडियन नॉलेज सिस्टम- आईकेएस सेंटर की ओर से प्राचीन भारतीय मंदिरों का आध्यात्मिक, दार्शनिक और स्थापत्य महत्त्व पर ऑनलाइन आयोजित 9वें राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। इससे पूर्व कॉन्क्लेव की शुरुआत सरस्वती वंदना के संग हुई। टीएमयू के वीसी प्रो. वीके जैन ने बतौर मुख्य अतिथि कहा, ऐसे कॉन्क्लेव भारतीय ज्ञान परंपरा को सशक्त बनाने और नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का माध्यम हैं। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति की जड़ों को समझे बिना आधुनिक भारत का निर्माण अधूरा रहेगा। लेखक, वक्ता एवम् पुस्तक समीक्षक श्री संदीप सिंह ने मंदिर अर्थशास्त्र पर बोलते हुए कहा, मंदिर आस्था, समाज और संस्कृति की त्रिवेणी हैं। मंदिर समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक चेतना हैं और उनका वास्तविक उद्देश्य मानवता, सेवा और आध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए, न कि धन या संसाधन प्रबंधन। श्री सिंह ने कहा, आधुनिक शिक्षा में ज्ञान के साथ नैतिकता और अध्यात्म का समावेश जरूरी है। उन्होंने मंदिरों की भूमिका की तुलना रेलवे नेटवर्क से करते हुए बताया, जैसे रेलवे देश को जोड़ता है, वैसे ही मंदिर समाज को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने वाला तंत्र हैं।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद सामने आई लापरवाही की ये तस्वीर, कहीं भारी न पड़ जाए अफसरों की अनदेखी

बाहरी दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। बाजारों में चौकसी बढ़ा दी है और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन सब के बीच कुछ सार्वजनिक स्थलों पर अभी भी सतर्कता की आवश्यकता है। मेट्रो स्टेशन के बाहर अब भी वाहनों खासकर ई-रिक्शा का जमावड़ा है। रिठाला और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर बेतरतीबी से खड़े ई-रिक्शा न केवल सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, बल्कि यातायात व्यवस्था के लिए भी सिरदर्द बने हैं। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इन स्थानों पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बाहर 30 से 40 ई-रिक्शा का जमावड़ा देखने को मिला। दोनों मेट्रो स्टेशन पर यातायात पुलिस का केवल एक जवान नजर आया। दैनिक जागरण ने बुधवार को इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बाहर का निरीक्षण किया। रिठाला मेट्रो स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से खड़े ई-रिक्शा का मजमा लगा दिखा। दोपहर तीन बजे यहां 50 से ज्यादा ई-रिक्शा का जमावड़ा नजर आया। इस कारण मेट्रो से बाहर आने वाले यात्रियों को रास्ता तक नहीं मिल पा रहा था। मेट्रो स्टेशन के आसपास यातायात जाम की स्थिति भी बन गई। रिठाला मेट्रो स्टेशन से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ाई जाते हैं। मेट्रो स्टेशन के लगभग एक से दो किलोमीटर के फासले पर सुखदेव महाविद्यालय, जिम्स कालेज समेत कई शिक्षण संस्थान हैं। जिनमें कई हजार बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसके अलावा रिठाला की फैक्ट्री में कामकाज के लिए लोग भी मेट्रो से आवाजाही करते हैं। सुबह और शाम के समय इस सड़क मार्ग पर भारी जाम की स्थिति देखने को मिलती है। रोहिणी की ओर से आने वाले वाहनों को रिठाला मेट्रो स्टेशन के आसपास भारी जाम का सामना करना पड़ता है। यहां यातायात पुलिस का केवल एक जवान दिखाई दिया। रिठाला मेट्रो स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। यहां भी कमोबेश रिठाला मेट्रो स्टेशन जैसा ही हाल देखने को मिला। शाम साढ़े चार बजे स्टेशन के आसपास भी 40 से 50 की संख्या में ई-रिक्शा का जमावड़ा देखने को मिलता है। यहां आसपास कई माल और अस्पताल है। लगभग आधा दर्जन माल, बड़ा होटल और दो बड़े अस्पताल भी है। यहां पुलिस का कोई भी जवान नहीं दिखा। लोगों ने बताया कि ई-रिक्शा के खिलाफ पहले भी कई बार पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पांच-सात दिन के बाद फिर यही ढर्रा लौट आता है। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद अब तो सचेत होना ही चाहिए। मैं बुधविहार में रहता हूं और मधुबन चौक महाविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रतिदिन रिठाला मेट्रो स्टेशन से सफर करता हूं। यहां लगभग 50 ई-रिक्शा हमेशा खड़े रहते हैं। जिनकी वजह से जाम भी लगता है। लालकिला के पास बम विस्फोट हुआ है। उसके बाद हमें भी डर लगता है कि यहां ई-रिक्शा वालों की वजह से को अनहोनी न हो जाए। क्योंकि यहां काफी भीड़भाड़ रहती है और इनकी वजह से काफी जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है।

दिल्ली ब्लास्ट : ईडी करेगी अलफलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच

नई दिल्ली ।

सरकार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की ईडी जांच के आदेश दिए हैं और यूनिवर्सिटी के खातों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने को कहा है. यह यूनिवर्सिटी दिल्ली विस्फोट मामले के बाद से जांच के घेरे में आई है. इस हमले से जुड़े डॉक्टर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. एनडीटीवी को शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज पर भी गौर करने को कहा गया है. बता दें कि दिल्ली धमाके की जांच एनआईए पहले से ही कर रही है. अब ईडी और ईओडब्ल्यू भी जांच में शामिल हो गए हैं.

सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए हैं. जबकि कई लोग घायल हैं. इस हमले में गिरफ्तार लोगों में अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े तीन डॉक्टरों भी शामिल हैं.

आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है

धमाके के अलग दिन यानी मंगलवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस में सर्च अभियान चलाया गया था. संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई थी. हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी में आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों को हम लगातार सहयोग कर रहे हैं और जो भी जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी जाती है, उसके बाद छापेमारी में हरियाणा पुलिस साथ दे रही है.

यूनिवर्सिटी से जुड़े एक ओर डॉक्टर की गिरफ्तारी

हापुड़ के जीएस मेडिकल कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया. जम्मू के रहने वाले है डॉक्टर फारूक ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस, एमडी की थी. पुलिस को इसके भी आतंकी संगठन से जुड़े होने का आशंका है.

एनएएसी से मिला नोटिस

इसके अलावा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने अल-फलाह विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कारण बताओ नोटिस में एनएएसी ने कहा कि उसने पाया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय, ''जो न तो मान्यता प्राप्त है और न ही उसने एनएएसी द्वारा मान्यता के लिए आवेदन किया है, ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है कि ''अल-फलाह विश्वविद्यालय अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रयास है, जो परिसर में तीन कॉलेज चला रहा है - अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (1997 से एनएएसी द्वारा ग्रेड ए), ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (2008 से) और अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (2006 से एनएएसी द्वारा ग्रेड ए)।

पीएम मोदी ने निर्यातकों के लिए 45,000 करोड़ की दो नई योजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के हालिया कैबिनेट फैसलों से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दो अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई।

पीएम बोले -मेड इन इंडिया की गूंज दुनिया में और तेज होगी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मेड इन इंडिया की गूंज पूरी दुनिया में और तेजी से सुनाई दे। कैबिनेट ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन को मंजूरी दी है, जिसके फायदे बताते हुए पीएम मोदी ने कहा- यह मिशन भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यह MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को मजबूती देगा। यह सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर परिणाम-आधारित प्रभावी तंत्र तैयार करेगा। इसके अलावा निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे व्यवसायों को सुचारू रूप से चलाने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

-: एक्सपोर्ट को मिलेगा बूस्ट : -

ग्रीन एनर्जी पर फोकस

मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे खनिजों की रॉयल्टी दरों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। ये खनिज हरित ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह निर्णय स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत न केवल निर्यात बढ़ाए, बल्कि वैश्विक बाजार में मेड इन इंडिया की पहचान को भी सशक्त बनाए।

45,000 करोड़ की ऐतिहासिक योजनाएं - अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्यातकों के लिए 45,000 करोड़ की दो नई योजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की।

उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। 25,060 करोड़ के इस मिशन से भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 20,000 करोड़ की इस योजना के तहत निर्यातकों को बिना गारंटी के ऋण की सुविधा मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि यह कदम MSME क्षेत्र को सशक्त करेगा और भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य की ओर ले जाएगा। यह फैसला अमेरिका में बढ़े शुल्कों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को राहत देने में भी मददगार होगा।

ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

लग्जरी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर चरणबद्ध तरीके से लगे बैन

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अहम सुझाव देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली लग्जरी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर विचार किया जा सकता है. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि सरकार भी इस विचार से सहमत है. सरकार इस दिशा में अग्रसर है. इस प्रोजेक्ट से 13 मंत्रालय सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सुझाव दिया. इस याचिका में सरकार की ईवी को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई है. जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि अब बाजार में बड़े और उच्चस्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन भी उपलब्ध है, इसलिए शुरुआत उच्च श्रेणी के पेट्रोल/डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से की जा सकती है. उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों में भी बड़े और आरामदायक मॉडल आ गए हैं. तो क्यों न पहले बहुत महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए? इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ऐसी गाड़ियां केवल बहुत कम लोग खरीद सकते हैं. सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि पहले इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें अधिक थीं, इसलिए प्रोत्साहन योजनाएं लाई गईं. अब मुख्य चुनौती चार्जिंग स्टेशनों की कमी है. इस पर कोर्ट ने कहा कि जैसे-जैसे सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी, चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी अपने आप बढ़ जाएगी. अदालत का कहना था कि ये सब बाजार से जुड़े मसले हैं. जब इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ेंगे तो चार्जिंग स्टेशन भी आएंगे. मौजूदा पेट्रोल पंपों पर भी वाहन चार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है.

मतगणना से पहले तेजस्वी की उम्मीदवारों संग बैठक, बोले- किसी गड़बड़ी से निपटने को तैयार

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी के उम्मीदवारों और जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की, जिसमें मतगणना से संबंधित दिशा-निर्देशों और मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। कथित चुनावी गड़बड़ी के आरोप दोहराते हुए, राजद नेता ने कहा कि पार्टी, बिहार की जनता के साथ, किसी भी प्रकार की अनुचित असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क, सजग और उत्साह, आशा और विश्वास के साथ तैयार है। तेजस्वी यादव ने हिंदी में ट्विटर पर पोस्ट किया कि कल रात पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना से जुड़े दिशा-निर्देशों और मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई।

6 नवंबर और 11 नवंबर को हुए 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुक्रवार, 14 नवंबर को होगी। उसी शाम विजेता की घोषणा की जाएगी, जिससे लगभग एक महीने से चल रहा चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। देश में दो दशकों में यह पहला विधानसभा चुनाव है जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद कराया गया। किसी भी असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए तैयार रहने की बात करते हुए, राजद नेता ने कहा कि लोकतंत्र की जन्मभूमि बिहार की न्यायप्रिय जनता और बिहार व संविधान से प्रेम करने वाले सभी सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता सजग, सतर्क, सतर्क और किसी भी प्रकार की अनुचित असंवैधानिक गतिविधि से निपटने के लिए उत्साह, आशा और विश्वास के साथ पूरी तरह सक्षम, जागरूक और तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और बिहारी लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले, पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में हेरफेर करने की कोशिश की जा सकती है। यादव के अनुसार, एनडीए मतगणना को धीमा करने के लिए सभी प्रयास करेगा और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते हुए लोगों में भय पैदा करने की कोशिश करेगा।

आरजेडी ने लगाया ईवीएम चोरी का आरोप, रोहतास डीएम ने किया खरिज, कहा- ट्रक में खाली बक्से थे

पटना।

रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उस दावे का खंडन किया जिसमें प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को मतगणना केंद्र के अंदर घुसपैठ से ले जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रक में खाली स्टील के बक्से थे। बुधवार देर रात, राजद कार्यकर्ता और समर्थक सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तकिया बाजार समिति परिसर में स्थित बज्र गृह मतगणना केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन करने और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए एकत्र हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, डीएम उदिता सिंह ने कहा कि कई उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की मौजूदगी में ट्रक की जाँच की गई। उन्होंने कहा कि ट्रक के सभी बक्से खाली पाए गए। सिंह ने कहा, कल शाम हमें सूचना मिली कि ईवीएम से भरा एक ट्रक बाजार समिति, तकिया में घुस गया है। यह सूचना मिलने के

बाद, हमने पाया कि एक ट्रक शाम 7:59 बजे बाजार समिति में घुसा था, और पुलिस ने उसकी पूरी जाँच की थी; उसकी प्रविष्टि लॉगबुक में दर्ज थी। प्रविष्टि में लिखा था कि ट्रक खाली बक्सों से भरा था। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीदवार, उनके अधिकृत कर्मचारी और उनके समर्थक वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद थे। उन सभी के सामने ट्रक को खोला गया, और उसमें कई स्टील के बक्से मिले। हर बक्सा निकाला गया, और सभी बक्से खाली पाए गए। पूरे ट्रक की जाँच के बाद, सभी बक्सों को उसी ट्रक में वापस लोड कर दिया गया। रोहतास के जिलाधिकारी ने सभी से 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया।

पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, आईएसआई के 10 एजेंट गिरफ्तार; बड़े अटैक की थी साजिश

लुधियाना। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में आईएसआई द्वारा संचालित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस बाबत डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई-पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमले के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस बाबत पुलिस ने विदेशी संचालकों के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी मलेशिया स्थित तीन गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित संचालकों के संपर्क में थे ताकि एक हथगोले को उठाने और उसकी डिलीवरी में समन्वय स्थापित किया जा सके संचालकों ने राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा था। पंजाब में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद को खत्म करने और सीमा पार आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

येदियुरप्पा को तगड़ा झटका, कर्नाटक हाई कोर्ट ने पोक्सो केस रद्द करने से किया इनकार, चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को संज्ञान लेने और समन जारी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह येदियुरप्पा की व्यक्तिगत उपस्थिति पर तब तक जोर न दे जब तक कि किसी भी स्तर पर यह आवश्यक न हो। साथ ही, अदालत से वह भी कहा कि वह उनकी ओर से दायर किसी भी छूट आवेदन पर विचार करे, सिवाय इसके कि जब कार्यवाही के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक समझी

जाए। उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि निचली अदालत को याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के आदेशों में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही मामले का निर्णय करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी स्वीकार्य आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें आरोपमुक्त करने की याचिका भी शामिल है। यह मामला एक नाबालिग की माँ ने दायर किया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी, 2024 को अपने बेंगलुरु स्थित आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी से छेड़छाड़ की थी। महिला और उसकी बेटी, यौन उत्पीड़न (बेटी पर) के एक पूर्व मामले और अन्य मुद्दों में न्याय पाने के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं। बाद में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण माँ की मृत्यु हो गई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द की, दलबदल कानून के तहत गई विधायकी

कोलकाता । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। मुकुल रॉय मई 2021 में भाजपा के टिकट पर सदन के लिए चुने गए थे, लेकिन उसी साल अगस्त में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए रॉय को राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य

घोषित कर दिया। अधिकारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के टिकट पर चुने जाने के बाद वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक फैसला है। यह वही याचिका है जो मैंने विपक्ष के नेता की हैसियत से दायर की थी। माननीय अदालत ने मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराते हुए स्पीकर द्वारा दिए गए पक्षपाती आदेश को भी रद्द कर दिया है। भले ही देर लगे, लेकिन सत्य की ही जीत होती है। संविधान और दसवीं अनुसूची की मर्यादा को बचाते हुए अदालत ने दलबदल मामलों में स्पीकर की पक्षपरता को स्पष्ट कर दिया है। मैं इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं।

दिल्ली विस्फोट पर सीएम उमर का बड़ा बयान- हर कश्मीरी आतंकी नहीं, कुछ ही लोग गुमराह!

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की निंदा की, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए थे। साथ ही, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा अपनाए गए शांति और भाईचारे के आदर्शों की भी पुष्टि की। दिल्ली में कथित आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ ही लोगों ने इस क्षेत्र में शांति और भाईचारे को नष्ट किया है और हर कश्मीरी को आतंकवाद से जुड़ा बताना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि यह बेहद निंदनीय है। कोई भी धर्म इतनी क्रूरता से निर्दोष लोगों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। जाँच जारी रहेगी, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए - जम्मू-कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है। ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ शांति और भाईचारे को नष्ट किया है। जब हम जम्मू-कश्मीर के हर निवासी और हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही विचारधारा से देखते हैं

और सोचते हैं कि उनमें से हर एक आतंकवादी है, तो लोगों को सही रास्ते पर रखना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा देने का आह्वान किया, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि निर्दोष लोग इससे दूर रहें। विस्फोट के आरोपियों के पेशेवर पृष्ठभूमि से होने, जिनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, पर टिप्पणी करते हुए, मुख्यमंत्री ने उस सुरक्षा चूक पर सवाल उठाया जिसके कारण यह विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा कि क्या हमने इससे पहले विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को नहीं देखा?... कौन कहता है कि पढ़े-लिखे लोग ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते? होते हैं। मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि उन्हें नौकरी से निकाल तो दिया गया, लेकिन उसके बाद किस तरह की जाँच की गई? मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया?... हम स्थिति को सामान्य बनाए रखने में केंद्र सरकार की मदद कर सकते हैं, और हम यही कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के कई निवासियों को कथित तौर पर एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसने संभवतः विभिन्न स्थानों पर कई आतंकी हमलों की योजना बनाई थी। इस बीच, ताज़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी एक आई 20 कार में बदरपुर बॉर्डर के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं।